RAJYA SABHA

Wednesday, 31st July 1996/9th Shravana 1918 (Saka),

The House met at eleven of the clock,
Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MTNL's Agreement with M&N Publications

*281. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether MTNL entered into an agreement with the M&N Publications in 1993 to bring out one supplementary and one main directory every year from 1993 onwards;

(b) whether MTNL has collected crores of rupees from the company for their advertisements in the yellow pages;

(c) whether the MTNL has failed to implement the agreement for bringing out the directory and supplementary; and

(d) if so, the reasons therefor?

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Sir, the contract in question was signed on 9th June 1993, and it was for a period of five years. The contract was for one main directory and one supplementary directory every year. The contract was signed for both the Bombay and Delhi directories. The actual faits are that whereas in the year 1993 only the supplementary directory was published, in 1994 the main directory was published but no supplementary directory was published. And, for the years 1995 and 1996, nothing has been published. It appears that every one has gone for holidays. It is said, I understand, that no directory was published for the years 1995 and 1996 as the required information was not supplied to M & N Publications. The contract with M & N Publications was, I understand, cancelled only a few days back, on 22nd July 1996. Now it will take another three or four months to find another suitable party, and that party will take another year before the directory is published. This means the directory will be published, at the earliest, only by the end of the year 1997.

Sir, my first supplementary consists of three parts—(a), (b) and (c) (a) Is it a fact that the required information was not supplied by the MTNL to M & N Publications, resulting in non-publication of the directory for the years 1995 and 1996? (b) Why didn't the MTNL, in case the directory was not published—whoever be at fault-take early action for cancelling the contract, and why did they delay this action till July 1996, which means a delay of almost three years, thus causing misery to people being without the directory for three years? (c) Why could not the MTNL themselves bring out at least a supplementary directory in each of these years, which was a comparatively simple job?

MR. CHAIRMAN: There are three questions.

MISS. SAROJ KHAPARDE: Three-in-one!

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन, आखिरी इश्यू दिल्ली और बम्बई टेलीफोन डाइरेक्ट्री का पब्लिश हुआ था नवम्बर 1994 में। यह सही है कि जिस कंपनी से करार हुआ था वह कंपनी डाइरेक्ट्री छापने में विफल रही है और उसका कारण यह रहा कि विभाग को वे रायल्टी देते थे और छपाई में जो तमाम पैसा लगता है वे वसूल करते थे येलो पेजेज विज्ञापन के जरिए। येलो पेजेज विज्ञापन के बारे में एक दूसरी कंपनी की तरफ से बम्बई हाईकोर्ट में रिट हो गयी। वहां रिट तो उनकी डिसमिस हो गयी लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हुआ कि येलो पेजेज कोई भी छाप सकता है। इसके कारण उस कंपनी को शायद लगा होगा कि उसको बहुत घाटा हो रहा है। इसलिए उस कंपनी ने डायरेक्टरी छापने में आनकानी की। विभाग बराबर उन के साथ बातचीत करता रहा और अप्रैल, 96 तक उन्होंने यह नहीं कहा कि हम डायरेक्टरी नहीं छापेंगे। इसलिए मजबूर होकर अब उन के करार को रद्द करना पड़ा है। अब गलती तो इस में हुई है और उपभोक्ताओं को

काफी असुविधा भी हुई है, इस में कोई दो राय नहीं है। उस के लिए कुछ और आल्टेनेटिव्ज निर्धारित किए गए हैं, लेकिन हम उन को पर्याप्त नहीं मानते हैं। इस में जो खास दिक्कत आई है वह "यलो पेजेज" के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है, उसी के बारे में आई है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यु पिटीशन मंजूर हो गयी है, लेकिन उस में भी देर लगेगी मैं यह कोशिश करूंगा कि अगस्त के महीने में और कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त के पहले हम नया टेंडर जारी कर दें। उस के बाद कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी नयी डायरेक्टरी छपकर उपभोक्ताओं को मिल जाय। अतः इस में कोई दो राय नहीं और हम आप से सहमत हैं कि कहीं-न-कहीं से लापरवाही हुई है और उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई है।

श्री कृष्ण कुमार बिरला: सर, मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने मान लिया कि गलती हुई है। बहुत कम मंत्री मान लेते हैं कि गलती हुई है। चूंकि मंत्री महोदय ने कहा कि गलती हुई है तो पहले क्युश्चन के बारे में मैं अधिक सप्लीमेंटरी नहीं करना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि—

I understand that the number of subscribers in Delhi is 12 lakhs, and in Bombay it is 15 lakhs. As a result of the non-publication of the directory, over 2 crores of people living in Bombay and Delhi, including visitors, have been put to immense difficulties. My second supplementary is whether, in view of the past experience and in view of the risks involved, the Government of India will in future follow a policy that no single party receives a contract for publishing directories for more than one major city so that in the event of non-compliance of the contract a vast number of people do not suffer hardships.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् यह जो करार हुआ था, यह एम०टी०एन०एल० बॉम्बे और एम०टी०एन०एल० दिल्ली, इन दो ही शहरों के लिए था। आप ने जो सुझाव दिया है, इस के बारे में परीक्षण करना पड़ेगा। लेकिन हम ने आज ही अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। दिल्ली और बॉम्बे के अधिकारियों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े इस के लिए जो हमारी 197 की सुविधा है, उस के संबंध में हम ने कहा है कि किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस कार्य के लिए लगाया जाए और 197 जब डायल किया जाय तो लोग उठाएं जरूर। श्रीमन् इस के अलावा एक दूसरा टेलीफोन नंबर 195 है। वह इसलिए है कि अक्सर बड़े शहरों में नंबर परिवर्तित होते रहते हैं। तो उस में आप सिर्फ 195 डायल करेंगे, पुराना नंबर बताएंगे और वहां से आप को नया नंबर मिल जाएगा। हम इन सुविधाओं को तेज करने की कोशिश करेंगे और नई डायरेक्टरी भी जल्दी छपवाने की कोशिश करेंगे। श्रीमन् आप ने कहा कि एक शहर के अलावा दूसरे शहर के किसी कंपनी को आदेश न दिए जाएं, इस में और कोई दिक्कत नहीं रही। उस कंपनी को नुकसान होने का भय होगा, इसीलिए उन ने इस तरह की लापरवाही और आनाकानी की। इस का विधिक परीक्षण करना पड़ेगा।

श्री शिवचरण सिंह: माननीय मंत्री जी आप को ज्ञात है कि पिछले वर्ष टेंडर घोटाले में डिपार्टमेंट की बड़ी भारी बदनामी हुई। अब यह डायरेक्टरी घोटाला भी उसी प्रकार का घोटाला है। आप ने डायरेक्टरी छपवाने के ऑर्डर दिए, लेकिन वह कंजूमर को पिछले तीन साल से मिली नहीं। तो आप यह बताने को कोशिश करेंगे कि इस में दोष का भागी कौन है? क्या विभागीय अधिकारीगण हैं और अगर वे दोष के भागी हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् इस में घोटाले से किसी बात को नहीं जोड़ना चहिए और हम घोटाले वाले हैं भी नहीं...**(व्यवधान)**... घोटाले के आरोप अगर हमारे ऊपर आएंगे तो मैं राजनीति से अलग हो जाना बेहतर समझूंगा। घोटाले की कालिख लगाकर मैं यहां पर बैठने की कोशिश नहीं करूंगा। श्रीमन् इस में हम ने पहले ही सही पोजीशन बता दी है। ...**(व्यवधान)**...अब आप पूरी बात सुन लीजिए। हम अभी आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 3 बार मंत्री रह चुका हूं और 6 बार एम०एल०ए० रह चुका हूं। ...**(व्यवधान)**... आप पूरी बात सुन लीजिए। इस में विभाग का कोई घोटाला इसलिए नहीं है कि यलो पेजेज से विज्ञापन कंपनी हासिल करती थी और उसी पैसे से इस में करोड़ों रूपए का खर्च होता है। विभाग उन को कुछ देता नहीं है बल्कि विभाग उन से रॉयल्टी लेता है। विभाग का इसमें कोई खर्च नहीं होता है बल्कि उसको आमदनी होती है और जो कंपनी छापती हैं वह येलो पेजेज के विज्ञापन से फायदा भी उठाती है और येलो पेजेज डायरेक्टरी भी छापती है। ...**(व्यवधान)**... आप पूरी बात सुन लीजिए। येलो पेजेज के बारे में बाम्बे हाई कोर्ट में टाटा ने एक रिट कर दी, जो रिट वहां

डिसमिस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में विभाग गया और सुप्रीम कोर्ट का उसमें यह फैसला हो गया कि येलो पेजेज को भी छाप सकता है। अब जब येलो पेजेज कोई भी छाप सकता है तो यह जाहिर है कि कंपनी को घाटा होता, इसलिए उसने आनाकानी की, लेकिन, अप्रैल, 1996 तक उसने यह नहीं कहा कि हम डायरेक्टरी नहीं छापेंगे। जब विभाग को यह मालूम हो गया कि यह आनाकानी ही कर रहा है तब जुलाई में उस करार को रद्द करना पड़ा और इनका करीब नौ/दस करोड़ रुपया जो उसका जमा हुआ था उसके जब्त किया गया।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, this problem is not confined to the main cities only where the telephones are run by the MTNL. It is the policy of the Government to privatise printing of telephone directories. Ever since the printing of telephone directory has been privatised, the standard of printing the telephone directory has gone down. All the names are misspelt. Even the abbreviations of the names of the Members of Parliament have been erased. As a result, the Department has no control over printing of telephone directories. Their main job is only to get advertisements. So, I want to know from the hon. Minister whether he would see to it that his Department maintains control over the private printing press; and also see that this contract is for a short-term instead of for five years or ten years, so that the standard of the directory is up to the mark.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: सभापति जी, माननीय सदस्य के सुझाव उचित हैं और उनको यथासमय लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 80 फीसदी जगहों में डायरेक्टरी छप रही हैं। कुछ जगह विभाग भी छपवा रहा है, लेकिन जो बड़े-बड़े शहर हैं वहां विभाग के पास इतना स्टाफ या उसको मैनेज करने के लिए जो बातें आवश्यक होती हैं वह शायद नहीं हैं, इसलिए बड़े शहरों में यह जो प्राइवेट कंपनी हैं यह विज्ञापन कलेक्ट करती हैं दूसरी कंपनियों से येलो पैजेज के लिए और उसके बाद उसे छापती हैं। इसमें भी अब जब यह मामला सामने आया है तो इसमें सुधार के लिए या कठोरता लेने की कोई आवश्यकता होगी तो उसमें हमारी तरफ से कोई हिचक नहीं होगी।

Telephones out of order in Delhi

*282. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of telephones went out of order in May/June 96 in Delhi and around;

(b) if so, the details of such telephones, exchange-wise;

(c) whether the so-called Monsoon Scheme for Cable Fault Status Information Service has since been put into action; and

(d) if so, the results thereof, and if not, the reasons therefor?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) कथित अवधि के दौरान एम०टी०एन०एल० और आस पास के क्षेत्रों में टेलीफोनों में कोई बड़ी खराबी नहीं हुई है। तथापि, दोषों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) मई और जून, 1996 के दौरान एक्सचेंजवार बुक की गई शिकायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ग) केवल दोष स्थिति सूचना सेवा ने 30.6.1996 से काम करना शुरू कर दिया है। यह सेवा मानसून की अवधि तक के लिए है।

(घ) यह सेवा, ग्राहकंन को उनके क्षेत्रों में केबल की खराबियों के बारे में सूचना देने तथा उन खराबियों को ठीक करने में लगने वाले संभावित समय की सूचना देने के लिए है।

† The Question has acutally asked on the floor of the House by Shri Parag Chalika.